भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4370
02/04/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

दुर्लभ पृथ्वी तत्व के भंडार और मैग्नेट विनिर्माण

4370 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्व के सबसे बड़े भंडारों में एक उपलब्ध है;
(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अग्रणी बनने के बजाय भारत की अन्य देशों पर निरंतर निर्भरता के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने हाल ही में मैग्नेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रूपये के दुर्लभ पृथ्वी तत्व से संबंधित योजना को अनुमोदित किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) भारत को मैग्नेट उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बनाने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक घटक इकाई ने देश में निम्नलिखित आरईई संसाधनों की स्थापना की है:

- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में टेरी, समुद्र तट रेत और इनलैंड एलुवियम में पाए जाने वाले 13.15 एमटी मोनाजाइट [थोरियम और रेयर अर्थ का एक खनिज] में लगभग 7.23 मिलियन टन (एमटी) स्व-स्थाने कुल रेयर अर्थ ऑक्साइड समतुल्य (टीआरईओ समतुल्य) मौजूद है।
- गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कठोर चट्टानी क्षेत्रों में 1.29 एमटी स्व-स्थाने आरईई संसाधन (टीआरईओ समतुल्य) हैं।

(ख) भारत आरई खनिजों के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं है। तथापि, भारत आरई मैगनेट और अन्य संबंधित उत्पादों के लिए निर्भर है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:

- भारतीय संसाधन ग्रेड (0.056% -0.058%) की तुलना में काफी कमजोर है और इसका संबंध रेडियोधर्मिता के साथ है और इस कारण इसे एक्सट्रैक्ट करना लंबा, जटिल और महंगा हो जाता है।
- सीआरजेड विनियम, मैंग्रोव, वन और अनियंत्रित आबादी के कारण खनन योग्य भंडार सीमित हैं जिसके कारण सीमित मात्रा में उत्पादन हो पाता है।

- हाई प्योर आरई ऑक्साइड से धातुओं, मिश्र धातुओं, मैगनेट आदि के निर्माण के लिए मिडस्ट्रीम आरई वैल्यू चेन वाले कम उद्योग होने के कारण रिफाइन्ड रेयर अर्थ की मांग कम होती है।

(ग)-(घ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर, 2025 को 'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' को मंजूरी दी और इसे 15 दिसंबर, 2025 को अधिसूचित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारत में सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) की प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन (एमटीपीए) मैन्यूफैक्चरिंग स्थापित करना है, ताकि आत्मनिर्भरता बढ़े और भारत को वैश्विक आरईपीएम बाजार में एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित किया जा सके।

इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 7,280 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच (5) वर्षों के लिए आरईपीएम बिक्री पर 6,450 करोड़ रुपये का बिक्री-लिंक्ड प्रोत्साहन और आरईपीएम विनिर्माण सुविधाओं के कुल 6,000 एमटीपीए की स्थापना के लिए 730 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है।

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) धरती पर उपलब्ध सबसे शक्तिशाली चुम्बकों में से एक हैं और ये इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस उपकरण और रक्षा प्रणालियों में आवश्यक घटक हैं। इस योजना का उद्देश्य देश के भीतर रेयर अर्थ ऑक्साइड की प्रोसेसिंग से लेकर धातुओं और मिश्र धातुओं के उत्पादन और अंत में परिष्कृत मैग्नेट का निर्माण करने तक एंड-टू-एंड आरईपीएम विनिर्माण क्षमताओं को स्थापित करना है।

(ङ) चुबंक के क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख देश बनाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित पहल की हैं:

- परमाणु ऊर्जा विभाग ने प्रतिवर्ष 3 टन समरियम कोबाल्ट (एसएमसीओ) मैग्नेट उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) संयंत्र स्थापित किया है जो आमतौर पर रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रदर्शन वाले रेयर अर्थ चुंबक हैं।

- आरईपीएम योजना में योगदान करते हुए, केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है।

*****